



International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 09, pp 684-689, September 2025

भारत-बांग्लादेश : स्ट्रैटेजिक ,सामरिक साझेदारी के बदलते आयाम

सुमित तिवारी

शोधार्थी , रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज)

सारांश

भारत ने बांग्लादेश की आजादी में ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनने में सहायता की थी। 1971 से लेकर वर्तमान तक दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद हुआ लेकिन इसका हल आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा किया गया। यही कारण की भारत और बांग्लादेश के बीच गहराते संबंधों के कारण स्ट्रैटेजिक, सामरिक भागीदारी का विस्तार किया गया है। आयुधो, सैन्य उपकरणों, लड़ाकू विमानों, आकाश मिसाइलें एवं अन्य सैन्य साजो समान के निर्यात हेतु भारत से सहयोग एवं सहायता की मांग लगातार बांग्लादेश करता रहा है जिससे युद्ध एवं विषम परिस्थितियों के कारण संकटकालीन स्थितियों में इनका उपयोग किया जा सके।

भारत आर्थिक क्षेत्र में ढील देते हुए व्यापार वाणिज्य उद्योग को बढ़ावा बांग्लादेश को देता आ रहा है रियायत दर पर वस्तु विनिमय होने से संरचनात्मक विकास करना उद्देश्य है परिवहन एवं सड़क कनेक्टिविटी से आवागमन, आयात-निर्यात में वृद्धि सस्ते माल एवं वस्तुओं जल्द से जल्द सीमा इस पार से उस पार भेजना , जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को और गहराई से समझा जा सके और उसको प्रागाढ बनाया जा सके।

ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत ने बांग्लादेश में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना में मदद की है , मैत्री गैस पाइपलाइन लगभग 134 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है इसे और विस्तार करने के लिए दोनों देशों के बीच अंतर सीमापार गैस पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, लघु बिजली ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थलों का निर्माण नए-नए इन्वैशन की खोज विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देते हुए रिश्तों में मधुरता सरलता लाने की आवश्यकता है।

परिचय

20वीं शताब्दी के चौथे और पांचवें दशक के मध्य भारतीय भू-भाग का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत पर किया गया। भारत का विभाजन

भू- राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया जिसका दुष्परिणाम आगे चलकर देखने को मिला। कुछ समय अंतराल के बाद 1950 से 1970 के दशक में ऐसा ही हुआ जिस कारण अंग्रेजों द्वारा “**बोया गया बीज उत्पन्न होता दिखाई दिया**”।

बांग्लादेश के उदय से ही भारत स्ट्रैटेजिक, सामरिक और संभारिक भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान में सत्ता प्राप्त करने के लिए एक ही देश की दोनों पार्टियों में विवाद उत्पन्न होने के कारण समस्या और जटिल हो गई जिसके कारण दोनों पार्टियों के बीच आंतरिक कलह, संघर्ष, लूटमार, जनसंहार होने लगा। इससे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान के दो भाग -पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) था। धार्मिक आधार पर पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) को एकता के सूत्र में बांधे हुए थे।

बीज शब्द :

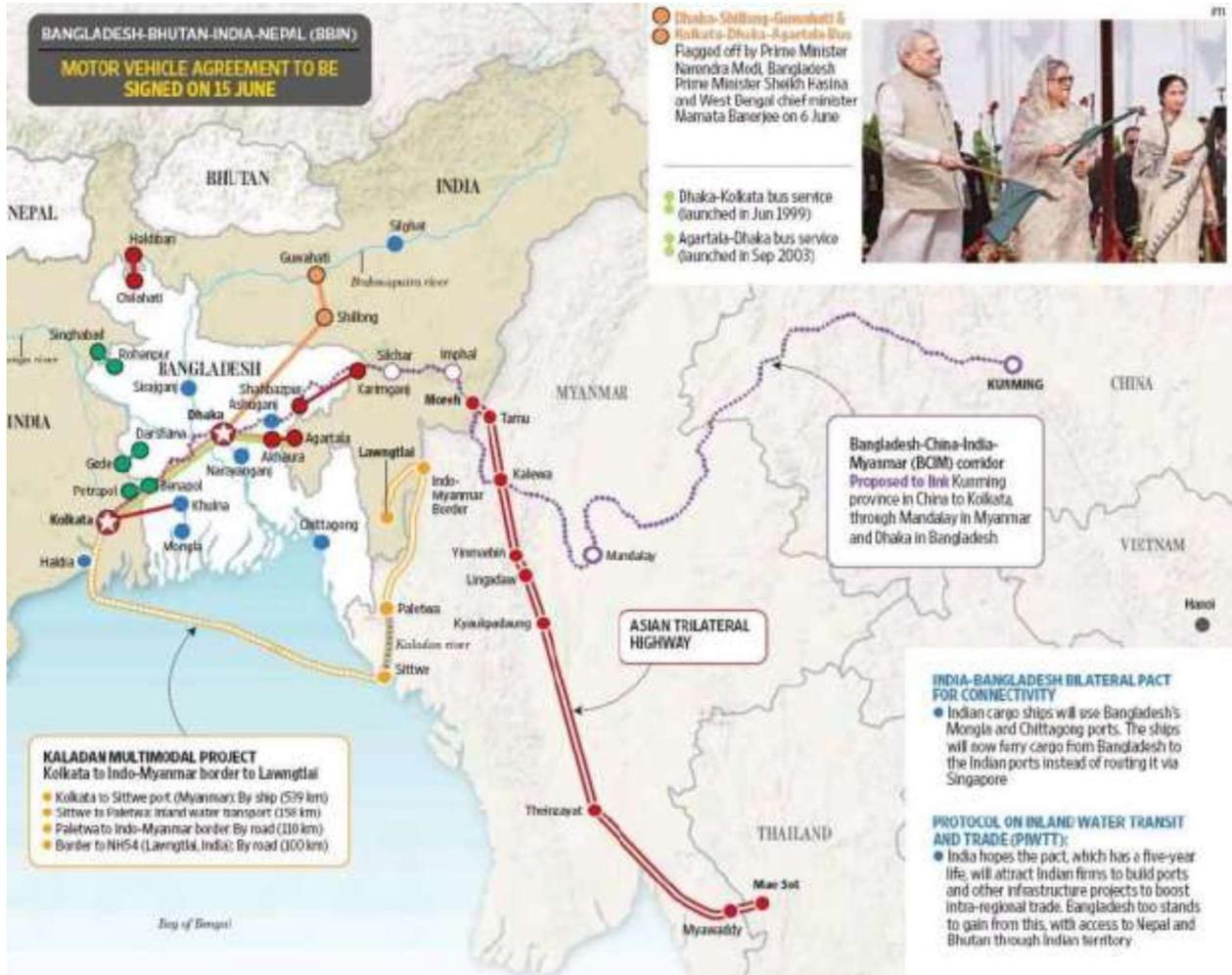
स्ट्रैटेजिक, सामरिक भूमिका, आंतरिक कला, संघर्ष, जनसंहार, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य प्रमुख, ऑपरेशन सर्वलाइट, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्षेत्रीय संघठन, मानवाधिकार, आत्मरक्षा।

विषय प्रवेश :

पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण निरंतर कर रहे थे। इस शोषण का विरोध पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुररहमान के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आम नागरिकों की हत्या, लूट-पाट, बलात्कार जैसी हिंसात्मक कृत्य बढ़ते देखे गए फिर आगे चलकर आम सहमति पर पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव में मुजीबुर रहमान भारी मतों से विजयी हुए, यह बात पाकिस्तान के राजनीतिकों, सैन्य प्रमुखों और आम नागरिकों को हजम नहीं हुई। आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट (टिक्का खां जो पाकिस्तान का कसाई) चलाया गया जिसके कारण बहुत संख्या में बंगाली, हिंदू, मुस्लिमान और अन्य धर्म के लोग अपने ही देश को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ये लोग सीमा पार करते हुए भारत में प्रवेश करना प्रारंभ करने लगे, देखते ही देखते कुछ माह में यह संख्या हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ तक पहुंच गई। भारत ने जब इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ, क्षेत्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, मानवाधिकार संगठन जैसे संस्थानों पर उठाया तो इन सभी संस्थानों ने मौन रहते हुए, भारत का आंतरिक मामला बतलाने के साथ नजर अंदाज किया। भारत को पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर सबक सिखाने का मौका मिला। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने अपने आत्मरक्षा एवं संप्रभुता को बचाए रखने के लिए पाकिस्तान के दोनों भागों में व्यापक हवाई हमला किया, इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और 93000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया इस युद्ध का परिणाम बांग्लादेश राष्ट्र का जन्म होना एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में भू सीमा समझौता किया गया। इस समझौता को आगे बढ़ाते हुए 5-6 जुलाई 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ (100वां संविधान संशोधन भारत में) सीमा को आदान-प्रदान करने के लिए यह समझौता जिसमें भारत ने 111 भू-भाग बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने 51 भूभाग भारत को दिया। यह एक ऐतिहासिक भू सीमा समझौता था जो दोनों देशों के आपसी सहयोग, परस्पर व्यवहार और क्षेत्रीय द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है। इस समस्या को हल करते हुए 2015 में न्यू मूरे दीप विवाद का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आया हुआ निर्णय दोनों राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से स्वीकार किया। भारत ने अपने पूर्वोत्तर भू-भाग को जोड़ने के लिए जून 2015 में म्यांमार के साथ कलादान मल्टी प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत की। यह मार्ग स्थल, समुद्र और नदी भारत के कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जल मार्ग द्वारा मिजोरम तक कलादान नदी द्वारा और मिजोरम से हाईवे सड़क द्वारा जोड़ा गया। भारत ने इस मार्ग का निर्माण व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन के अतिरिक्त युद्ध, आपदा एवं विषम परिस्थितियों में सिलीगुड़ी काली डोर गलियारा (चिकन नेक) का एक विकल्प के रूप में रखा है।

दोनों देशों द्वारा द्वि पक्षीय और बहुपक्षी समझौते के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी समझौता, तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना एवं संचार, डाटा संचार का आदान-प्रदान किए जाने पर सहमति बनी। स्थल, जल, वायु मार्ग सीमा पर आतंकवादी, उग्रवादी, अवैध हथियारों सामानों की निगरानी करने के लिए सीमा प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं।



स्थलीय सीमा प्रबंधन के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों द्वारा निगरानी सीमा पर चार दिवारी, तारबंदी, कैमरा (दिन एवं रात्रकालीन), अंडर ग्राउंड थर्मल इमेज आदि का प्रयोग बॉर्डर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त 2018-19 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में स्मार्ट **बाड** का उद्घाटन किया। जल सीमा प्रबंधन हेतु सोनार, अंडरग्राउंड इमेज, नदी, बांध का निर्माण किया गया है। टारपीडो, गस्तीपोत, समुद्री गश्ती जहाज से निगरानी की जा रही है। वायु क्षेत्र से छोटे, बड़े ड्रोन के द्वारा अवैध हथियारों सामग्री को सीमा उस पार से इस पार भेजा जा रहा है, इसकी निगरानी के लिए सैटेलाइट, ड्रोन, एंटी ड्रोन, राडार, लेजर, फोटो इमेज आदि से निगरानी भारतीय वायु सीमा क्षेत्र द्वारा की जा रही है।

भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 2017 में बंगबंधु उपग्रह छोड़ा। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ावा मिलेगा 2015 में क्षेत्रीय जीपीएस उपग्रह प्रणाली में सहयोग देने योग्य एक उपग्रह छोड़ा गया। इस उपग्रह प्रणाली से स्थल, जल, वायु की निगरानी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा सीमा प्रबंधन, शांति, सहयोग, भाईचारा बना रहेगा। भारत अपने प्रथम पड़ोस नीति (2004) मेक इन इंडिया 25 सितंबर (2014) सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति के द्वारा सैन्य सहयोग, सैन्य उपकरण पनडुब्बी, हथियार, गोला, बारूद और अन्य रक्षा रक्षा उत्पादन सामग्री बांग्लादेश को उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में तेजस फाइटर विमान, समुद्री गश्ती पोत समझौता किया जा रहा है, तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास, संप्रीती, बोंगो सागर वार्षिक नौसैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। युद्ध, आपदा एवं संकटकालीन परिस्थितियों में इन सेनाओं द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है।

आर्थिक स्टैटिजिक :

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तीनों शपथ समारोह (2014 से 24) कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आमंत्रित किया, केंद्र सरकार प्रथम पड़ोसी, मेक इन इंडिया कार्यक्रम (2014) भारत निर्माण, रिकल इंडिया, न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के प्रयास से बांग्लादेश और भारत का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत बांग्लादेश के मध्य व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और धंधे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो दोनों देश लगातार 6% जीडीपी से अधिक वृद्धि कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य रेल कनेक्टिविटी

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल लिंक 17 दिसंबर 2020 को पांच स्थानों से जोड़ने हेतु कार्य किया गया। इसकी शुरुआत पेट्रयो(भारत)बिनापोल (बांग्लादेश),गेडे(भारत)दर्शन (बांग्लादेश),सिंहबाद (भारत),रोहनपुर (बांग्लादेश), राधिकापुर (भारत),तिरोल (बांग्लादेश) में किया गया। अखौरा (बांग्लादेश),अगरतला रेल संपर्क 1 नवंबर 2023 में 12.24 किलोमीटर की तथा हल्दीबाड़ी और चिनहट को जोड़ा जा रहा है 1 नवंबर 2023 को चटगांव मोगला पोट को जोड़ने हेतु भारत से समझौता किया गया है जो 65 किलोमीटर लंबी यह सड़क का निर्माण किया गया है जून 2015 को भारत बांग्लादेश के बीच कोलकाता- ढाका-अगरतला बस सेवा प्रारंभ किया गया 2019 में दिल्ली से ढाका के लिए यात्री वायु परिवहन को खोला गया उपयुक्त स्थल को ,जल,वायु परिवहन प्रणाली को कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना है, जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापार, उद्योग और पर्यटन में गत्यात्मक परिवर्तन देखने को मिले और साथ ही साथ रणनीतिक रूप से पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के विकल्प के रूप में जोड़ने का कार्य पूर्ण हो सके।

भारत आसियान संगठन (1967),सार्क(1985),बिस्स्टेक(1997), एक्ट ईस्ट पॉलिसी (2014),अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ(1945)अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, गैर सरकारी संगठन,अंतर सरकारी संगठन और डब्ल्यूटीओ के सहयोग से व्यापार,वाणिज्य,उद्योग,धंधों, पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देते हुए दोनों देश संयुक्त रूप से विकासशील से विकसित देश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के कारण भारत और बांग्लादेश के मध्य लगातार बिगड़ते रिश्तों से व्यापार वाणिज्य में कमी आयी है। स्थल मार्ग से भारत ने बांग्लादेश के व्यापार में कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, बांग्लादेश में अस्थाई अंतरिम सरकार के कारण दोनों राष्ट्रों के बीच रिश्तों में कड़वाहट होने के कारण इसका फायदा चीन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र :

पिछले एक दशक से देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ऊर्जा एवं व्यापार में काफी उन्नति होती प्रतीत हो रही है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 131.57 किलोमीटर का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को वर्चुअल माध्यम से दोनों देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा उद्घाटन किया गया। यह पाइपलाइन सिलीगुड़ी (नुमाली रिफाइनरी)से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक जाती है। 1 नवंबर 2023 को रामपाल मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के दो यूनिट (1320)मेगावाट को बनाने में भारत ने सहायता किया। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजना, परमाणु बिजली उत्पादन हेतु साझेदारी की बात चल रही है। ऊर्जा किसी देश के विकास में आर्थिक,सामाजिक,एवं बुनियादी ढांचों की और संरचनात्मक निर्माण में सहयोग एवं सहायक की भूमिका अदा करती है। संयुक्त रूप से सरकार मिलजुल कर ऊर्जा आवश्यकता को आपूर्ति का कार्य कर रहे हैं, इससे दोनों देशों के मध्य रणनीतिक ऊर्जा सहयोग,सहायता और साझेदारी में बढ़ोतरी हो रही है और दोनों देश अपने आर्थिक विकास की गति पर निरंतर वृद्धि कर रहे हैं।

पर्यटन :

भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने की शुरुआत एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है। दोनों राष्ट्र, धर्म के अलग होने के बाद भी सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के आदान-प्रदान करते रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी गंगा विशाल क्रम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह क्रम अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा

3200 किलोमीटर पांच राज्यों, 27 नदियों से होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। इससे वैश्विक स्तर में हमारी समृद्धि रियासत और बढ़ेगी क्योंकि पर्यटक भारत की आध्यात्मिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक के साथ जैव विविधता की समृद्धि बढ़ावा प्रदान करता है। कुछ पर्यटक स्थलों जैसे ढाका,कासबाजार,सुंदरवन,दार्जिलिंग,सिलीगुड़ी,साइंस सिटी,कालिमपोंग आदि स्थलों को जोड़कर पर्यटन से धन प्राप्त किया जा सकता है।

नदी- जल विवाद

बांग्लादेश के आजादी से पूर्व ही दोनों देशों के मध्य नदियों का विवाद बना रहा लेकिन फरक्का नदी जल विवाद 1974 द्वितीय 1996,तीस्ता नदी जल विवाद जल समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास दोनों राष्ट्र संयुक्त रूप से कर रहे हैं मोदी जी ने एक वक्तव्य में कहा था “भारत और बांग्लादेश के मध्य 100 से अधिक ऐसी नदियां हैं और उसकी उप सहायक नदियां हैं” जो सीमा विवाद कर रहे हैं इनका हल जल्द ही ढूंढ कर निराकरण किया जाएगा। हाल ही में भारत बांग्लादेश के मध्य कुशियारा नदी और फेनी नदी का विवाद का हल ढूंढ कर समस्या का निराकरण किया है। इससे दोनों देशों की सरकार लगातार संयुक्त रूप से मिलकर सहयोगात्मक सहरानी कार्य कर रही हैं।

चीन का स्ट्रेटेजिक महत्व :

चीन हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में विस्तारवादी नीतियों के द्वारा अपना पैठ बनाने की तलाश में रहता है चीन अपनी चालाकी भरी चाल से साजिश द्वारा स्थल मार्ग होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करना चाहता है। वह अपनी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, प्रसारवादी, हड़प नीति, सैन्य हस्तक्षेप, कर्ज नीति (लोन नीति) के माध्यम से पड़ोसी देशों को चंगुल में फंसाने का प्रयास करता रहता है। वह बीसीआईएम (बांग्लादेश चीन भारत और म्यांमार), वन बेल्ट वन रोड (बी आर ए 2013) स्थल वायु, जलमार्ग के रास्ते संरचनात्मक निर्माण कर रहा है। सड़क, पुल, नदी, बंदरगाहों, हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी करते हुए इस क्षेत्र में आना चाहता है। चीन बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह, म्यांमार के कोको दीप श्रीलंका का हब्बनतोता बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करके स्ट्रिंग आफ पल्स पॉलिसी (2004) के द्वारा भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है।

वह आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक रूप से भय, आशंका का माहौल बनाए रखना चाहता है। उसकी मनसा एशिया में एकल ध्रुवीय होने की है। चीन बांग्लादेश को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता, आर्थिक छूट, कर्ज, कर, शुल्क, प्रशुक्र को छूट देकर आर्थिक चंगुल में फसाना चाहता है।

माओ का कथन है - “मछली को फसाने के लिए जल में चारा डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार की चाल वह चलकर आगे बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों को फसाते हुए भारत को घेरना चाहता है, उसकी यह नीति सहयोगी, दोस्ती, हमदर्द का नाटक खेल खेलते हुए वह भारत को आर्थिक सैन्य रूप से कमजोर करना चाहता है। वह राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाना शुरू करता है और सत्ता के प्रलोभन में आकर यह विकासशील देश मजबूर होकर अपने पतन, हवाई द्वीप, सड़क एवं भूमि को लीज पर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 2020 के दशक से ऐसा ही देखने को मिला है - श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, सत्ता पलट जैसी स्थितियाँ सामने आयी हैं।

निष्कर्ष

भारत और बांग्लादेश के बीच गहराते संबंध में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। वर्तमान घटनाओं से बांग्लादेश में आंतरिक कलह के कारण शेख हसीना सत्ता पार्टी को पद से बेदखल करते हुए अगस्त 2024 को अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूसुफ की ने शपथ लिया, इससे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से दोनों राष्ट्रों को क्षति उठाना पड़ा है। सीमा प्रबंधन करने के लिए सड़क, रेल, वायु कनेक्टिविटी का उचित प्रबंध किया गया है। आतंकवादी, उग्रवादी सीमा का उल्लंघन न कर सके इसलिए आपसी विश्वास और भाईचारा बनाकर दीर्घकालिक सफर तय करना सुनिश्चित किया गया है, आगे चलकर बाहरी शक्तियों को इस क्षेत्र में आने से रोकना है, क्षेत्र में शांति बनी रहे यह दोनों राष्ट्रों का उचित कर्तव्य होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- सलाम आजाद, “बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान” प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट, न्यू दिल्ली (2014)
- ईयान कारडोजो मेजर जर्नल, (अनुवादक विनोद कुमार मिश्रा) “भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास” प्रकाशन, प्रभात नई दिल्ली (2023) पेज संख्या (244)
- कपूर एस के, “मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि” प्रकाशन, सेंट्रल लॉ एजेंसी प्रयागराज, (2022) पेज संख्या (947)
- बहियां अब्दुल बद्दू द इमरजेसी ऑफ बांग्लादेश एंड रोले ऑफ़ अवामी लीग प्रशासन विकास पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली 1982
- भारद्वाज संजय के इंडीज बांग्लादेश बॉर्डर गवर्नेंस इश्यू एंड चैलेंज इस प्रशासन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 2016
- दास पुष्पित “इंडियाज अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट फ्रॉम बैरियर टू बिग्रेडस, प्रकाशन पब्लिशर टेलर एण्ड फ्रांसिस (2023)
- कुमार महेंद्र, “अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष” प्रकाशन, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा, पेज संख्या (361)।

पेपर:

- द हिंदू 6 अगस्त 2024,
- द हिंदू 17 फरवरी 2024

ई - श्रोत :

- संसद टीवी : https://youtu.be/3wCtQdg_nW4?si=e6QmHZRqmYsDYyqy
- www.bsf.nic.in
- www.pib.